

>

Title: Further discussion on the resolution regarding formulation of an Action Plan to rehabilitate persons displaced from Pakistan, moved by Shri Arjun Meghwal on 17August, 2012 (Resolution Negated).

श्री गजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदया, लगभग तीन महीने पूर्व 14 दिसम्बर को इस संकल्प पर चर्चा ढो रही थी। मैं एक बार पुनः इस संकल्प को दोहराना चाहता हूँ - पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करें।

महोदया, इस संकल्प पर बोलते समय मैंने सदन के ध्यान में इस बात को लाने का प्रयास किया था कि पाकिस्तान में यह यहे हिन्दुओं के संबंध में पाकिस्तान सरकार जो कहती है और पाकिस्तान की सरकार उनके साथ जो व्यवहार करती है, उसमें बड़ा भारी फर्क है। मैंने यह बात बताने की कोशिश की थी कि यदि हम कहे पर विश्वास करेंगे और जो वहां ढो रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम वहां के हिन्दुओं के प्रति न्याय नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इसके अनेक उदाहरण हैं, विभिन्न परिकारों के माध्यम से जो कुछ मानवाधिकार संगठन, जो पाकिस्तान के अंदर कार्य करते हैं, छातांकि उनकी आवाज बड़ी ढब्बे हुई रहती है, उन्होंने विभिन्न परिकारों के माध्यम से जो उल्लेख किए हैं, उनमें भी इस बात की पर्याप्त वर्चा है कि पाकिस्तान के अंदर हिन्दुओं की स्थिति बहुत खराब है। उनको किसी भी प्रकार की आजांटी नहीं है।

महोदया, मुम्बई में सेन्टर फोर ह्यूमन राइट्स रेटरीज एंड अवेयरनेस नामक संगठन काम करता है। उसने इसका व्यापक अध्ययन किया है। उसका निष्कर्ष यह है कि सामान्यता सम्पूर्ण पाकिस्तान के आम आदमी के अंदर इस प्रकार की आवाज बैठायी गयी है, विभिन्न माध्यमों से, शिक्षा के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, संविधान में शंशोधन के माध्यम से, ज्यूलिशियरी के माध्यम से, जो वहां का परस्पैशन है, वह यह है कि हिन्दुस्तान भारता नंबर एक शतू देश है। हिन्दुओं का एक मातृ घर यहि कोई बचता है, तो वह हिन्दुस्तान बचता है, इसलिए हिन्दुओं के प्रति शतू भाव को लेकर वह व्यवहार करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज भी हमने जो सर्वसम्मति से प्रत्याव पास किया है, वह इस बात की पुष्टि करता है कि पाकिस्तान कुछ भी कहता है, वहां के नेता कुछ भी कहते हैं, कितनी भी सदाशयता उनका रखाने में हम दिखाते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु उसके तौर-तरीके में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता। मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों की जो घटनाएं हैं, वह इसकी पुष्टि करती हैं।

महोदया, यदि मैं संक्षेप में वर्णन करूँ तो हिन्दुओं के खिलाफ जो वातावरण वहां है, उसके परिणामस्वरूप वहां महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। रिकल कुमारी, आशा कुमारी के प्रकरण विश्व विस्त्र्यात है, इसे सभी लोग जानते हैं। मैं इंडिया ट्रुडे का एक लेख आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। अप्रैल, 2011 को एक व्यक्ति श्री मेहरबांध यहां आए थे, वे अपने साथ लगभग 135 डिल्ले ले कर आए थे, जिनमें उन हिन्दू लोगों की शर्क थी, जो वहां मेरे थे, ताकि उनकी शर्क को यहां गंगा जी में प्रवाहित कर सकें। उन्होंने एक बात कही कि मेरी पत्नी वर्ष 2009 में केंसर से मर गई और अपने पीछे लो बेटियां छोड़ गईं। पत्नी की मृत्यु के बाद एक सुबह मैंने पाया कि मेरी छोटी बेटी जो उस समय 16 साल की थी, वह गायब है। पूछताछ करने पर मुझे बताया गया कि वह अपने से उम्र में काफी बड़े गुड़े के साथ भान गई है। वह यात्रों-रात इस्लाम धर्म में धर्मार्थित हो गई। कुछ जुर्जुरों के फरतक्षेप से मुझे उससे मिलने की इजाजत ती गई। वह योते हुए मेरी छाती से टिपक गई। मुझे लिलकुल विश्वास नहीं था कि वह भान गई है। वह गुंडा मेरी बेटी पर नज़र रख रहा था। मैंने बड़ी बेटी की शादी समय रहने कर दी थी और छोटी बेटी अभी बढ़ती थी। काश मुझमें आड़स होता और मैं अपनी बेटी के लिए लड़ पाता। रथानीय पुतिस ने इसमें मेरी कोई सहायता नहीं की।

सभापति महोदया, ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनको ठीक से पढ़ पाना भी संभव नहीं है और जिनको सुनकर भी दिल ढक्कता है। इसी प्रकार से वहां हिन्दुओं के शीति-रियाज हैं यानी यदि उनका कोई रितोदार या कोई उनका परिवार में मरता है तो वे शवदान नहीं कर सकते। किसी त्याहार पर कोई शोभायात्रा नहीं निकाल सकते। पूजन नहीं कर सकते। यानी यह रिति वहां पर है। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं उनको कोट करके अक्षरशः नहीं कहना चाहता हूँ। वर्षोंकि जो लोग वहां से भागकर आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि हम छोटा-मोटा काम करते थे। जो उनके मुस्तिम ग्राहक थे, उन्होंने यह सोचकर कि यह तो हिन्दू है, इसलिए इसका रूपया वापस देने का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने उसका पैसा देना बंद कर दिया और उनकी पूँजी समाप्त हो गई और वे लुट-पिटकर भारत आ गये। यानी आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से सब प्रकार से हिन्दुओं का उत्पीड़न वहां पर हो रहा है। दुनिया के अंदर मानवाधिकार संगठन हैं। हम रखने यानी भारत मानवाधिकारों के लिए बहुत तड़ता है। यदि किसी को कुछ संकट होता है तो हमारे प्रधान मंत्री जी को कई बार यात को नीट भी नहीं आती है। अच्छी बात है। इतना संवेदनशील होना चाहिए। परंतु यह हैरान है कि हिन्दुओं की इस दशा के प्रति सरकार संवेदनशील वर्षों नहीं होती? वहां जो छिन्दू हैं, मानवाधिकार यानी उनको जीवन का अधिकार नहीं है, विवाहों की आजांटी नहीं है, सम्पत्ति का अधिकार नहीं है और यहां तक कि न्याय प्राप्त करने की भी उनको छूट नहीं है, जैसे मैंने अभी एक प्रकरण में दो लड़कियों का जिक्र किया था। जो उनके प्रकरण से प्रकट होता है।

सभापति महोदया, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन्स ने रिप्यूजी की एक परिभाषा दी है। मैं उस परिभाषा को पढ़ना चाहता हूँ। इस परिभाषा में कहा जाया है:

"Refugees are people who are forced to flee from their countries because of threats to their life linked to their race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion."

यह यूनाइटेड नेशन्स के द्वारा दी गई शरणार्थी की परिभाषा है। मैं नहीं समझ पाता कि यह परिभाषा पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं पर लागू होती है। या नहीं होती है। तो किन वे से अपराध उनको शरणार्थी मानने को तैयार नहीं हैं। यह सरकार उनके किसी भी सुख-दुख को समझने को तैयार नहीं है। जबकि मैं इससे भी आगे जाकर एक बात और कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिन्दू ये वो लोग हैं जो देश के विभाजन के समय हमारे नेतृत्व पर भरोसा करके वहां पर रह गये थे। उनका कोई अपराध नहीं है। बाट में जो नेढ़ल लियाकत समझौता हुआ और जो सारी बातें हुईं, उनके ऊपर भरोसा करके वो वहां पर रहे और यदि वे

अपनी मूलभूति के अंदर आना चाहते हैं तो शरणार्थी के नाते भी जो अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषा है और मानवीय कर्तव्य के नाते भी तथा हमारे नेताओं के द्वारा दिये दुए वाए के अनुसार भी उनको सम्मान पूर्वक इस देश के अंदर जगह दी जानी चाहिए। ऐसा मेरा आपसे बहुत विनम्र आश्रू है।

मैंने प्रायः मैं ही कहा कि अखिर हम पाकिस्तान के व्यवहार को वर्णों नहीं देखते? उसके कथन पर वर्णों भरोसा करते हैं? मुझे तगड़ा है कि कहीं हमारी सोच में वोट-बैंक की राजनीति धुसी ढुक्क है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि हम छिन्दुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केवल छिन्दुस्तानी वर्णों नहीं समझते? भारतीय वर्णों नहीं समझते?

अभी अफजल गुरु का मसला हुआ। पहले हम उनको फांसी नहीं दे रहे थे। फिर हमने फांसी दे दी। वोट-बैंक के हिसाब से हमने अफजल गुरु को मुरितम माना। हम उसको केवल यह मानते कि उसने हमारे देश के प्रति अपराध किया है और नियम के अनुसार, कानून के अनुसार उसको उसके अपराध के लिए जो सजा होनी चाहिए, वह उसको मिलनी चाहिए। हम वर्णोंकि छिन्दुस्तान के नागरिक को छिन्दू या मुसलमान मानते हैं, हम वर्णोंकि वोट पर निगाह रखकर अपने फैसले रखते हैं और वर्णोंकि पाकिस्तान में रहने वाले छिन्दुओं की विंता करके हम वोट-बैंक में कोई वृद्धि नहीं कर सकते, संभवतः केवल इस कारण से पाकिस्तान का छिन्दू उपेक्षित है और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जब तक सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देगी और जब तक हम अपनी गौलिक सोच को नहीं बदलेंगे कि एक तुष्टिकरण के लिए, एक वोट-बैंक की राजनीति के लिए ही हम किसी खास वर्ण की विंता न करें, बल्कि यह सोचकर कि किसी खास वर्ण को भी हमारी तरह तकलीफ होती है, ऐसा सोचें। यह कैसे मान तिया गया कि यदि अफजल गुरु को फांसी दी जर्ह तो यारा मुसलमान तबका नाराज हो जाएगा? यह बात सच नहीं है। कुछ लोग होंगे। ऐसे लोग सब जगह होते हैं। जब राजनीति या राजनीतिक निर्णय इस तरह के दबाव में होते हैं तो वोट बैंक की राजनीति के परिणामस्वरूप उन लोगों की विंता भी नहीं कर पाते जिनकी विंता करना हमारा कर्तव्य है।

मठोदया, यही कारण है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंत्र ही वर्णों न हो, हमने इस विषय को नहीं उठाया है। एम्बेसी इंटरनेशनल, व्हैमेन राइट्स संगठन में कभी पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की दशा का संज्ञान ही नहीं दिया है वर्णोंकि हमने कभी मामला उठाया ही नहीं है। जबकि उनके लिए इन सब समस्याओं का बहुत ही फिटस्ट केस है, जिसका अध्ययन करना चाहिए, छस्तक्षेप करना चाहिए तोकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की है। सार्क में पाकिस्तान भी है, हमने कभी इस मुद्रे को वहां नहीं उठाया। जैसा कि मैंने प्रायः में कहा कि मानवाधिकार के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे नेतृत्व का भरोसा करके यदि वे आना चाहते हैं, उनकी विंता करें। वहां के गृह मंत्री ने कह दिया कि वीज़ा गतत जारी किया गया। इस तरह की स्थिति में न वीज़ा दिया जाएगा और न सुख चैन से रहने दिया जाएगा तो उनकी विंता कौन करेगा? हम इस बात को उठाएं, यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इन विषयों को उठाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसका संज्ञान लेंगे तभी इस समर्या का हल होगा।

मठोदया, मैं कुल मिलाकर सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय की गंभीरता को समझो। पाकिस्तान में हिन्दुओं को शरणार्थी के नाते जो वहां से भागकर आए हैं, उन्हें उचित रूप से नागरिकता प्रदान करें। इसके साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि वे सुरक्षित नहीं हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से सुरक्षित जीवन दिया जाए।

प्रौ. सौनत शय (दमदम): माननीय सभापति मठोदया, मैं अर्जुन शम मेघवाल द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ बल्कि इसलिए कि उन्होंने संघर्ष में अपने क्षेत्र की समस्या को बहुत धीर्घपूर्वक रेख किया है। यह हमारे लिए सीखने की बात है कि कैसे अपने क्षेत्र की समस्या के विषय को उठाया जाता है। मुझ से पहले माननीय सदरय बीजेपी के बोते हैं। मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ वर्णोंकि उन्होंने बहुत से डिवाइसिंग इश्यू उठाए हैं। अफजल गुरु, इसके साथ क्या ताल्लुक है? उन्होंने फिर वोट बैंक की बात की। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें करने से समस्या हल नहीं होती है। मेरे रखाने से यह समस्या माननीय समस्या है।

मठोदया, आप जानते ही हैं कि देश का बंटवारा हुआ, बंगाल का बंटवारा हुआ और पंजाब का बंटवारा हुआ। पंजाब में जनसंख्या का एवसरेज द्वारा जबकि बंगाल में नहीं हुआ और बहुत से हिन्दू ईर्ष्ट पाकिस्तान में रह गए। अभी भी बांला देश में 90 तारख के करीब हिन्दू हैं। कुछ ऐसे डिस्यूथे थे जो पूरे पाकिस्तान में रहे थे। ऐसा ही एक डिस्यूथ है, आडावानी जी जहां से आते हैं, कराची से और एक एरिया बहावलपुर एरिया है। सिंध का बंटवारा नहीं हुआ था। इसलिए पूरा सिंध वाला गया और यहां के लोग दिल्ली, मुम्बई में आए और अब ज्यादातर सिंधी लोग कपड़े का व्यापार करते हैं। मेघवाल जी ने जिस सवाल पर सबका ध्यान आकर्षित किया वह बहुत ही गरीब लोगों के बारे में है। भीत और मेघवाल एसी लोग हैं। ये लोग लेजिटिम वीज़ा लेकर छिन्दुस्तान आए थे। ये पाकिस्तान नागरिक ज़रूर थे तोकिन यहां आकर वापस नहीं जाना चाहते थे। यह बात सर्वी है कि पाकिस्तान में बहुत फ़ंडामेंटिस्ट लोग हैं। पाकिस्तान में जो हिन्दू बहुत थे उन पर बहुत ज़ुल्म दुष्ट इंडिया टुके में 'छिन्दूज इन पाकिस्तान' बहुत बड़ा आर्टिकल बिकता कि कैसे अत्याधिकार होता है। ये लोग वापस नहीं जाना चाहते थे, इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। करीब 17,000 लोग खास तौर से जोधपुर में ट्रिजिट कैप में रहते हैं।

मेघवाल जी के प्रस्ताव के मूल सवाल के अनुसार वह चाहते हैं कि इसे नॉर्मलाइज किया जाए। हमारे प्रांत में जो प्रॅब्लम थी, उसमें हम तारखों लोग इधर आये और वहां हमने कट ऑफ डेट 1971 रखी थी। बंगालदेश के जन्म तक हम कहते हैं कि 1971 कट ऑफ डेट है, तोकिन लोगों का आना-जाना बंद करना मुश्किल है, हमारा पोरस बार्डर है, इसलिए हम लोगों को आने से रोक नहीं सकते। तोकिन अभी भी हम बंगाल या आसाम में कानून के जरिये ठोस रास्ता निकाल सकते हैं। तोकिन जो लोग हुए 17 हजार लोग हैं, उनमें मैंने सुना है कि भीत और मेघवाल में से कुछ लोग जम्मू-कश्मीर में रहते हैं। ये सब हिन्दू हैं, शेड्यूल्ड कारस्ट हैं और नागरिक अधिकार की प्रार्थना करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन जी जवाब देंगे, वह एक मानवीय दण्डिकाण वाले आदमी हैं और वे सोच-विवार कर इन लोगों की समस्या का निगरानी करने की कोशिश करेंगे।

यहां यूनाइटेड नेशंस कंफैनेशन कैरेक्ट के बारे में बताया गया, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, वर्णोंकि रिप्यूजीज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बंगालदेश में शेड्यूल्ड लोग भागकर आये हैं, वे मुसलमान हैं, जो म्यांगार में रहते हैं, वही लोग आते हैं। रिलीजियस परसीक्यूशन के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना एक पुरानी परम्परा है और यूनाइटेड नेशंस डाईकमिंशर फॉर रिप्यूजीज द्वारा एक व्यापार विकास करते हैं कि किनते ऐसे रिप्यूजीज रिलीजियस परसीक्यूशन के लिए आये हैं। मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता। श्री अर्जुनराम मेघवाल जी बीकानेर से सांसद हैं और वे लोग जोधपुर में अधिक संख्या में रहे हैं, वर्णोंकि जोधपुर एक बड़ा शहर है। आप जैसलमेर जाइये, वह भी बार्डर है, वहां भी जोधपुर से जाना पड़ता है। यदि बीकानेर जाओ तो भी जोधपुर से जाना पड़ता है। जोधपुर के

आसपास ये लोग बसे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हूँमेनिटेरियन ट्रिटकोण से इस समर्थन का निदान किया जाए और मुझी भर लोगों को हिंदुस्तान में नागरिक अधिकार दिया जाए।

इन बातों के साथ मैं मेघवाल जी के प्रस्ताव का राजनीतिक ट्रिटकोण या वोट बैंक के कारण से नहीं, बल्कि हूँमेनिटेरियन ट्रिटकोण से समर्थन करता हूँ।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकान्ता): महोदया, श्री अर्जुन मेघवाल जी जो प्रस्ताव लेकर आये हैं कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में ऐसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समर्थनाओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा आग्रह करती है कि उन्हें नागरिकता प्रदान करने हेतु तत्काल कदम उठाया जाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों के समान अन्य सुविधाएं मुहैया कराये जाने के लिए सरकार योजना तैयार करें। ऐसा जो प्रस्ताव मेघवाल जी लेकर आये हैं, उसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ और समर्थन देता हूँ।

आजादी के समय छमारा देश एक अखंड हिंदुस्तान था। लेकिन दुर्भाग्यवश छमारे देश का पक्षिम पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान और भारत तीन भागों में बंटवारा हो गया। तब ऐसा माना जाता था कि जो जहां चाहता है, वह वहां रह सकता है। तब बहुत से लोग पक्षिम पाकिस्तान से भारत आये, बहुत से लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये, लेकिन उस वक्त डारों की संख्या में कम्त हुए। जिनके कारण छमारी आजादी का जप्त दुखाद बन गया। आजादी के समय पाकिस्तान में 75 लाख हिंदू थे, लेकिन आज सिर्फ 18 लाख बचे हैं। आज पाकिस्तान की आबादी 17 करोड़ है, इसमें पहले 27 प्रतिशत हिन्दू थे, लेकिन अब सिर्फ दो प्रतिशत ही बचे हैं। पाकिस्तान से हिंदुओं का बढ़ता पतायन एक जम्भीर चिंता का विषय है। छमारे हिंदू वहां से क्यों पतायन कर रहे हैं? वे अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं। वे अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, बल्कि मज़बूती में हिंदुस्तान आ रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है। लड़कियों को किडनैप कर के ले जाते हैं और मुस्लिम युवकों के साथ उनकी शादी करवा देते हैं। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके कारोबार को बंद कर देते हैं। इतना प्रताङ्गित करते हैं कि उसकी वजह से वहां बसे हिंदू लोग भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार उनको आने के लिए वीजा नहीं देती है। इसलिए वह तीर्थ यात्रा के नाम पर कि छम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, छोड़ जाने दीजिए, तब वे अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ कर छमारे देश में आते हैं। आने के बाद वे अपना दुख छमारे सामने व्यक्त करते हैं कि वहां पर छमारी कोई सलामती नहीं है। ... (ल्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : The time allotted for the discussion on this Resolution is over. If the House agrees, the time may be extended by one hour, including for the Minister's reply.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Madam.

MADAM CHAIRMAN: The time for the discussion on the Resolution is extended by one hour.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: हिंदूओं को वहां सुरक्षा नहीं मिल रही है। उनको लूटा जाता है। उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। महिलाओं के साथ भी बलात्कार किया जाता है। इन सब मुश्किलों की वजह से जब हिंदू हिंदुस्तान में आ जाते हैं, तो उनको संरक्षण मिलना चाहिए। जो हिंदू पाकिस्तान से आते हैं, वे ज्यादातर राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर के आस-पास आ कर बसते हैं। पहले वे छमारे देशवासी थे, छमारे भाई हैं, छमारे बंधु हैं। छमारी मांग है कि उनको नागरिकों का अधिकार मिलना चाहिए और इस भूमि पर उनको रहने की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए ताकि वे सही ढंग से रह सकें।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदया, मैं मेघवाल जी के रेजल्यूशन के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। छमारे देश में सद्व्यवहार और सौदार्द का वातावरण रहा है। छमारे देश ने दुनिया को आश्रय दिया है। छमारे ऋषियों की यह प्राथमिका रही है कि -

"सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया।
सर्वे भव्याणि पश्यन्तु मा कथित् दुखाभाग् भवेत्।"

यहां सब की मंगल कामना की गई है। त्रैता युग में जब जनकपुरी में भीषण अकाल पड़ा, तब वहां की जनता अयोध्या में आ कर बसी। अयोध्यावासियों ने उनको आश्रय दिया। भारत ने तिब्बतियों को अश्रय दिया। जिस समय लंका अशांत था, लंका के निवासियों को, तमिल भाइयों को भारत के पूर्व प्रधान मंत्री रवर्णीय राजीव गंधी जी ने भारत के अंदर आश्रय दिया। लेपाल में भी जब कठिन दौर चला तब लेपालियों को भी भारत ने आश्रय दिया। पाकिस्तान में वर्ष 2008 में 160, 2009 में 104, 2010 में 373, 2011 में 478 और अप्रैल 2012 में 370 हिंदूओं को मार डाला गया। हाल ही में 9 जनवरी 2013 को पाकिस्तानी ईजर दो भारतीय यैनियों के सिर काट कर अपने साथ ले गए। इस प्रकार का एक यिनौना वातावरण बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के छमारे हिंदू भाइयों को निश्चित रूप से भारत में शरण मिलनी चाहिए।

हिंदू शब्द का उद्गम सिंधू शब्द से हुआ है। सिंधू याटी के अंदर रहने वाले लोग, वर्योंकि फ़ारसी के अंदर 'स' को 'ਛ' लोता जाता है, इसलिए सिंधू का न कह कर के उनको हिंदू कहा गया। छमारे मोहनजोद़ों और हड्डपा की जो सभ्यता है, उसका भी उत्थान छोना चाहिए। जिससे छम सब को यह पता चले कि छमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। जिस समय हड्डपा की सभ्यता पनप रही थी, उस समय हड्डपा और मोहनजोद़ों की सभ्यता से कफ़े बन कर मिटू के फ़ैले के लिए जाया करते थे।

16.00 hrs.

इसी प्रकार से जब हमारी सभ्यता वरम सीमा पर थी, तब मेसोपोटामिया की सभ्यता पनप रही थी। इतनी प्राचीन सभ्यता के बारी हम लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भारत में निश्चित रूप से शरण मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

MADAM CHAIRMAN: The next speaker is Shri Ashok Tanwar. You would be allowed to speak only for two minutes.

श्री अशोक तंवर (सिरसा): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने आपको हमारे गाथी अर्जुन गम मेघवाल जी के बिल के साथ सम्बद्ध करता हूँ और साथ ही साथ उसके ऊपर ज्यादा वर्चा न करते हुए केवल एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी कांस्टीचुंरी जो सिरसा संसाधीय क्षेत्र है, जब पाकिस्तान का हिंदुस्तान से विभाजन हुआ और कशीब-कशीब जो 30 से 35 प्रतिशत आबादी जो वहां से माइग्रेट होकर आई, उनके तो बहुत सारे जवान भुजे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी वर्ती बहुत से माननीय सदस्यों ने की है। इसके साथ-साथ हमारे कुछ साथी ऐसे हैं, जैसे सिरसा जिले में एक अतनाबाद तहसील है, जहां कशीब 66 परिवार वर्ष 1992 में आये। आज भी उनकी नागरिकता का एक बहुत बड़ा मुठा है। पहले उनका वैलिड वीजा होगा, फिर उसके बाद केन्द्र में मामला आएगा, मैं आपके माध्यम से सदन से यही आग्रह करना चाहता हूँ... (व्यवधान) इसीलिए अर्जुन जी, मैंने अपने आपके साथ सम्बद्ध किया है, ताकि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि इनको हम अधिकार दे सकें और आने वाले समय में इनको हिंदुस्तान की नागरिकता के माध्यम से ज्यादा सुविधायें प्रदान कर सकें।

MADAM CHAIRMAN: Thank you.

Now, the hon. Minister to reply to the discussion.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): Madam, I am deeply grateful to the hon. Members of this august House who have actively participated on the Resolution moved by Shri Arjun Meghwal for the formulation of an action plan to rehabilitate persons displaced from Pakistan.

Altogether, 14 hon. Members have taken part in the discussion, and I thank each one of them. I place on record my deep appreciation for their valuable suggestions and observations. I have carefully listened to the speeches made by each Member, and I have taken note of all the important points raised by the Members. I once again thank them for their valuable suggestions and observations.

I fully share the sentiments expressed by the hon. Members of this august House. Now, I may try to reply to almost all the important points raised by the hon. Members. I wish to take up the key issues one by one.

A very important issue has been raised by Shri Meghwal relating to the rehabilitation of displaced Hindu families presently coming from Pakistan. It is worthwhile to mention that in order to solve the massive problem of mass influx of displaced persons from the erstwhile West Pakistan -- as a result of partition in 1947 and to rehabilitate them -- the Government of India, during 1950's, had taken a series of measures by enacting a series of Acts. As the major works of claims, compensation and also rehabilitation, more or less, had been completed by 1970, the Central Government repealed all these Acts in 2005. At present, we do not have any Act in this connection because this august House has repealed all these Acts.

I would like to state that the Central Government has been very sensitive to the issues faced by the Pakistan nationals who migrated to India at various point of time. For instance, it has been decided that the cases of the Pakistan nationals who entered India prior to 31.12.2004 would be processed on a case to case basis, and if an applicant files an Affidavit before the authority prescribed under Rule 38 of the Citizenship Rules, 2009, that is, the Collector, District Magistrate and Deputy-Commissioner, it may be accepted in lieu of the Renunciation Certificate. The State Governments and UTs concerned have been duly requested to deal with these matters as per instructions given by the Ministry of Home Affairs. In fact, the Ministry has also stipulated a Standard Operating Procedure for dealing with foreign nationals who claim to be refugees. The gist of the procedure is as follows:

- (i) The version of the foreign national making such claim will be carefully examined by the concerned FRRO/FRO. The FRRO/FRO will recommend the matter to the Ministry of Home Affairs (MHA) for grant of Long-Term Visa within thirty-days from the date of claim by the foreigner provided it is found that *prima facie* the claim is justified on the grounds of a well-founded fear of persecution on account of race, religion, sex, nationality, ethnic identity,

membership of a particular social group or a political opinion.

- (ii) MHA will consider all the inputs including the report of FRRO/FRO as well as inputs of the Ministry of External Affairs (MEA) and arrive at a decision on Long-Term Visa with validity up to one year from the date of issue. Details of cases in which Long-Term Visa is ordered will be shared by the MHA with MEA.
- (iii) The Long-Term Visa for such foreigners will be renewed every year for a maximum of five years at the level of the FRRO/FRO concerned based on assessment of the conduct of the foreigner and security implications. In case of any adverse report is arrived at, the MHA will be immediately taking appropriate action in this connection.
- (iv) During such period of stay in India, the foreigner national will be allowed to take up any employment in the private sector or undertake studies in any academic institution in our country.
- (v) No such foreigner will be deported without the permission or specific clearance of the MHA.
- (vi) No person who is an economic immigrant will be entitled to the benefits of these guidelines.

Another important issue has been raised by Shri Meghwal and other Members relating to rehabilitation of West Pakistan refugees of 1947 who have settled down in Jammu & Kashmir (J&K). The hon. MPs -- during the course of the debate -- have highlighted various grievances and demands of West Pakistan refugees of 1947 who have settled in the State of Jammu & Kashmir.

In the wake of Pakistan aggression in Jammu and Kashmir in 1947, about 4,745 families have migrated from the then West Pakistan and were settled in Jammu, Kathua and Rajouri Districts of Jammu Division. After their migration, some of these families occupied Government land and evictee property land. The State Government, in fact, allowed them to retain up to 8 acres per family of irrigated land or 12 acres of un-irrigated land subject to certain conditions.

The West Pakistan refugees settled in Jammu & Kashmir are not permanent residents of the State in terms of Jammu & Kashmir Constitution. Consequently, they do not enjoy the benefits that other residents of the States are entitled to. These West Pakistan refugees of 1947 are very much the citizens of India as they have the right to cast their vote in Parliament elections.

The Government of India has requested the State Government from time to time to confer the benefits of State subject on West Pakistan refugees and to consider the issue of Permanent Resident Certificate to these refugees. The matter is under the domain of the J& K administration, and as all of you are aware that we cannot directly intervene in the matter of J&K because J&K enjoys special status in view of Article 370 of our Constitution.

In order to mitigate the problems of West Pakistan refugees, the hon. Prime Minister announced a package for J&K in 2008. The package provides for concession to children and grandchildren of West Pakistan refugees settled in J&K in matters of admission in technical and educational institutions approved by the All India Council of Technical Education (AICTE). The All India Council of Technical Education (AICTE) has issued guidelines for creating necessary provisions in this connection. The State Government of J&K has also been advised to cover the West Pakistan refugees under various Centrally-sponsored schemes that are being implemented in the State of J&K.

This Ministry has advised the Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises to impress upon the member lending institutions such as public sector banks located in the State of Jammu and Kashmir to extend credit facility to West Pakistan refugees under the Credit Guarantee Scheme.

Another important question has been raised by hon. Members relating to permission to Pakistani nationals residing in border areas to visit the West of National Highway-15 in Rajasthan. I think, Madam, you have also raised this issue the other day. The Government has examined the request for grant of permission to Pakistani nationals residing in the border areas to visit the West of National Highway-15 in Rajasthan. As you know, Madam, it falls in the protected area. On security considerations, it has not been possible to grant such blanket permission to the Pak nationals to visit that area. However, such requests of Pakistani nationals received through the State Government of Rajasthan are examined on a case to case basis in consultation with security agencies for grant of requisite permission.

Madam, another important issue has been raised, that is, delegation of power to the District Collectors in the States of Gujarat and Rajasthan for grant of Indian Citizenship to Pakistan nationals. This is a very important issue which has been raised by some Members. The powers to grant Indian Citizenship to nationals of Pakistan belonging to minority Hindu community were delegated to the Collectors of Kutch, Patan, Banaskantha, Ahmedabad of Gujarat and Barmer and Jaisalmer of Rajasthan in 2004 for one year to grant citizenship to Pak nationals of minority community staying in the

border districts of Rajasthan and Gujarat as a special case. This delegation was extended up to 2007 on year to year basis. Such powers were not delegated to any other State. Sufficient time was given to these two States to decide such pending cases.

Madam, I may mention that some of the cases were received by the Ministry of Home Affairs where Indian Citizenship was granted to Pak nationals without renunciation of Pak nationality which may result in dual nationality. This is against our Constitution. Such lapses have security implications also. You are fully aware of that.

The provisions of applying for Indian Citizenship continue to be available as per provisions of Citizenship Act of 1955. Normally, the Central Government takes about four months in processing cases and issuing acceptance letter in consultation with security agencies. In order to make the procedure simpler, faster and transparent, the Home Ministry has decided to introduce what is called online submission of application for grant of citizenship with effect from 1.12.2001.

Another important issue has been raised about the fee structure. A reasonable fee of Rs. 5,500 was prescribed for citizenship under Section 5 (1) (a) of Citizenship Act, 1955 in 2005. This is a one-time payment for acquiring Indian Citizenship. We consider it to be quite reasonable.

Another very important issue, that is, permission to go to other cities in India for livelihood, work permit, marriage, death or any other important work was raised by the hon. Members. I am extremely happy to inform the House that Pakistan nationals staying in India on long-term visa are permitted to engage in employment of purely private in nature. Similarly, children of such Pak nationals are also permitted to take admissions in schools, colleges and universities subject to usual conditions prescribed for foreign nationals in this regard. On security considerations, it may not be possible to grant blanket permission to visit other cities. However, Pakistani nationals on long-term visa can get requisite permission for visiting other places through the State Government concerned.

Madam, a very important issue has been raised by almost all the hon. Members, that is, the condition of the Hindu minorities who are living in Pakistan.

As such, I cannot give any assurance on that. The issue has been taken up by the Government of India from time to time with Pakistan Administration. Through diplomatic channel alone, we can take up that issue. Right now, I can tell you that much.

Madam, coming to the question of deportation of Pakistani nationals belonging to Minority communities in Pakistan, again I would like to say that this issue will be taken up at the level of Pakistan Government through diplomatic channel by the Government of India.

I am happy to reassure that till the proposal for grant of a long term visa is under consideration, Pakistani nationals will not be deported to Pakistan.

I would like to reiterate that the Government of India is very sensitive to the issue related to the welfare of all foreign nationals in India including Hindu Pak nationals who deserve support and attention subject to the laws of the land and policies of the Indian Government.

I once again thank hon. Arjun Meghwalji, Madanlal Sharmaji, your honour Shrimati Sumitra Mahajan, T.K.S. Elangovan Ji, Shri B. Mahtab, Dr. Baliram, Dr. Mirza Mehboob Beg, Shri Choudhary Lal Singh, Shri Kabindra Purkayastha, Shri S.D. Shariq, Rajendra Agrawal Ji, Prof. Saugata Roy, Shri Mahendrasinh Chauhan, Shri Satpal Maharaj and Shri Ashok Tanwar for their contribution. Everybody has contributed a great deal to this live discussion. I thank everyone for their contributions and for their suggestion/observations.

In view of these facts stated by me, I earnestly request the hon. Member MeghwalJi to withdraw his resolution.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): पाकिस्तान में जो हिन्दू परेशान हो रहे हैं, उनको भी भूख लगी है, उनकी भी चिन्ता करें और उसके बारे घर जाने की योचे, ये सब छारे साथी हैं, ये इस चर्चा में यहां बैठे हैं, इसलिए मैं इनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदया, मैं अभी मंत्री जी का जवाब बहुत सावधानी से सुन रहा था, ये काफी मेहनत करके आए हैं, आम जैसे कोई मंत्री रिप्लाई देता है, उस तरह से इनका रिप्लाई नहीं था, आपने काफी मेहनत करके रिप्लाई दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद द्वूँगा, लेकिन मेरे चार-पांच प्लाईट ऐसे थे, जिनको आपने बहुत ढंग से एड्रेस नहीं किया, मेरे सिर्फ पांच प्लाईट्स हैं, मेरे जो राजस्थान के साथी बैठे हैं, इन्हें सब पता है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर इस समस्या से वाकिफ नहीं हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, सौन्तर राय जी वाले गए, जौधापुर में ही ट्रिजिट स्टेशन है, राजस्थान की सरकार ने भी कुछ रिकोमेंडेशन की है, मेरा यह कहना था कि पहले यह पता लगाइए कि कितने पाकिस्तानी नागरिक राजस्थान में रह रहे हैं, क्या उसका कोई सर्वे कराएं? इसका आपने कोई जवाब नहीं दिया,

गजरस्थान के अलावा वे गुजरात में कितने रहे रहे हैं? सभापति जी आप खवरं जड़ों से आते हैं, इन्होंने में कितने रहे रहे हैं? भारत के अन्य भागों में वे कितने रहे रहे हैं और वे क्यों रहे रहे हैं, वे क्यों नहीं पापस जाना चाहते हैं? इसका सर्वे करा के एक टिस्ट बनाते, उसका इसमें आपने कोई जवाब नहीं दिया।

दूसरा मेरा इश्यू बड़ा महत्वपूर्ण और मार्मिक था। उसका सारांश यह था कि नेशनल कमिशन फोर जिस्टिस एंड पीस की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमें यह तिरका हुआ था कि पाकिस्तान में हिन्दुओं की न जिन्दगी सुरक्षित है, न इज्जत। आप इसमें विनता नहीं करेंगे खाली यह कह देने से, they are Pakistani nationals. It is not sufficient Minister Sir. ये वे तोग हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। जब देश के टुकड़े हुए, तब वे वहां रह गए। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, कई लोगों से मैं मिला हूं। मेघवाल, शील, चारण, राजपूत और सिंधी समाज के भी वे तोग हैं।

मैं उनसे मिला हूं, वे कहते हैं कि हमारा वया कस्तूर था। मेघवाल और शील तो यह कहते हैं कि हम मजदूरी करने के लिए बढ़ावलपुर जये हुए थे और जब डिवीजन हुआ, हम डिवाइड हुए तो हमें कठा गया कि आप यहां रहो, कोई प्रौलाम नहीं है। अभी राजेन्द्र अग्रवाल जी सही कह रहे थे, नेहरू-लियाकत समझौता हुआ, बोले कि आपको कोई तकलीफ नहीं हैं, आप यहां पाकिस्तान में आराम से जिंदगी बसाए कर सकते हैं। आज उनकी छातत वया है, आज छातत यह है कि वे किसी के यहां काम करते हैं तो उनको कहते हैं कि आप को मजदूरी नहीं दी जाएगी तो वे कहते हैं कि वया दोगे, वे कहते हैं कि खाली खाना खाओ और गुजर-बसर करो। वया आदमी खाली खाना खाने के लिए वहां रहेगा? उसकी वया गलती थी? मैंने ऐस्यू रिकॉर्ड देखा है, एज ए डी एम भी देखा है और उसमें अगर आप तीन पीढ़ियां पहले जाओगे तो वे तोग यहीं के रहने वाले थे, हमारे बीकानेर, जैसलमेर, बांगेर, फतौरी, जोधपुर, यहां के रहने वाले लोग थे। वे मजदूरी करने के लिए वहां बढ़ावलपुर चले जये और उस समय जब इनको कठा कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, यहां रहिये तो वे वहां रह जये। उनकी वया गलती है? आज वे तकलीफ में हैं।

ये तोग कोई भगोड़े नहीं हैं, वे कोई आग कर नहीं आ रहे हैं। ये वे तोग हैं, जो पासपोर्ट से आ रहे हैं, वीजा से आ रहे हैं, कोई रामदेव जी के दर्शन करने आ रहे हैं, कोई हिंगलाज़ माता के दर्शन करने आ रहे हैं, ये वे तोग हैं। अभी कुम्भ में मेला हुआ तो वे कुम्भ में रनान करने के लिए आये, ये वे तोग हैं। वे जोधपुर, जड़ा से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, वह उनका गृह जिला है। वहां वे ट्रिंजिट कर रहे हैं और वहां ट्रिंजिट कर रहे हैं तो जो जोधपुर की जनता है, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जोधपुर की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वह इतने लोगों का प्रबन्ध कर सकती है। वहां टेट लगा हुआ है, उनको खाना खिला रहे हैं, उनके रहने की, नडाने की, धोने की व्यवस्था की जा रही है। अभी मेरे ठीक सामने अशोक तंपर साहब बैठे हैं, एतनाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर और एस.पी. साहब ने उनको धमकाया, वे कई सालों से वहां एलनाबाद में रह रहे थे तो वहां पर एक लोक सीमांत संगठन के हिन्दू सिंह सोङा हैं, उन्होंने कठा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप यहां जोधपुर आ जाइये। एलनाबाद से भी 100-125 लोग जोधपुर में बैठे हैं, वहां शरण लिए हुए हैं। जब कोई प्राइवेट आदमी शरण दे रहा है, वहां प्राइवेटली जोधपुर के लोग उनको शरण देने के लिए मैनेज कर रहे हैं तो भारत सरकार उन लोगों को शरण वयों नहीं दे सकती, मेरा यह यक्ष प्रूज़, सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से हैं। Why can you not do it when the private people are doing it?

मंत्री जी, यह कोई साधारण इश्यू नहीं है, यह बहुत गम्भीर विषय है। मेरा यह कठना है कि आप पांच बिन्दुओं के बारे में तो कम से कम मुझे आशासन तो देते, आपने मेरे से अपील कर दी कि आप इसको विशद्ग्रा करिये। कभी-कभी सरकार को यह योवना चाहिए कि जब कोई गम्भीर विषय एक प्राइवेट ऐजेंट्सूजन के नामे कोई एक मैम्बर लाता है तो सरकार को गम्भीरता से उस पर विवार करना चाहिए। आपने अपने जवाब में कठा, हम यह वया मांग रहे हैं, हम चार-पांच चीजें मांग रहे हैं कि इनको शरणार्थी का दर्जा दे दिया जाये। आप उनको रिप्यूज़ी रेटेस वयों नहीं दे सकते, I cannot understand it! वे तोग अनडिवाइडिंग फैमिली के ही तोग हैं और वे डिवाइड होने के बाद वहां चले गये या वहां रह गए। उनके पुरुषों देखोने तो उनके पुरुषों की यहां जमीनें हैं। गोपाल सिंह जी शेखावत मेरे आसी हैं, वहां बैठे हैं, इनके कई रिलोटिव मुज़े ओसियां में मिले थे, उन्होंने कठा कि वे चारण समाज के लोग वहां चले गये, उनके दादा यहां रहते थे। आप अगर ऐस्यू रिकार्ड देखोगे तो इनके दादा और उनके दादा में खाते हैं। फिर आप उनको रिप्यूज़ी रेटेस वयों नहीं दे सकते? मेरा आपसे कठना है कि उनको शरणार्थी का दर्जा वयों नहीं दे सकते, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया।

दूसरा मेरा यह पाइंट था कि सिटीज़नशिप वयों नहीं दे सकते, वे वहां नहीं जाना चाहते। मंत्री जी, आपको पता है, मैंने प्र्यास किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्र्यास किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां गये, मैं यहां इस मंच से कठना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां गये और कांग्रेस पार्टी के लोग भी वहां गये। उन्होंने सब ने समझाया, उन्होंने कठा कि वह नहीं जाएंगे, वयोंकि, हमारी बहन-बेटी वहां सुरक्षित नहीं हैं। हम पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, लैकिन वहां नहीं जाएंगे। अगर वे नहीं जाएंगे, तो वया जीने का अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा? वया हम जबरदस्ती उन्हें वहां भेजेंगे कि आप मरने के लिए पाकिस्तान जाइए?

महोदय, यह बात ठीक नहीं है। जब मैं उनसे जाकर मिला तो बहुत मार्मिक पीड़ा होती है, उसमें बत्ते भी हैं, महिलाएं भी हैं, छोटे-छोटे बत्ते भी हैं। ये जो एलनाबाद से आये हैं, उनके तो साथ में बत्ते हैं, उनको एलनाबाद से खटेड़ दिया गया, अब जोधपुर वाले सुरक्षा करने वाले नहीं हैं, शरणार्थी शिविर चलाने वाले नहीं हैं तो वे कहां जायेंगे? मेरी दूसरी बात यह थी कि आप उन्हें नागरिकता वयों नहीं दे सकते और यह अधिकार आप डीएम को वयों नहीं दे सकते? आपने कठा कि वर्ष 2004 से वर्ष 2007 तक हमने डीएम को अधिकार दिया था, तो आपने इसकी प्रूफिंग को इतना जिटिल वयों रखा? अब तक कुछ नागरिकताएं मिली हैं, तो कुछ और भी तो लेते। अब ये जो लोग आये हैं, ज्यादातर रिकल केस के बाद आये हैं। यह जो रिकल केस हुआ, उससे आए हैं, ये उन्होंने नहीं बुलाये हैं। आप यह यमज़ रहे होंगे कि हम उन्हें बुला रहे हैं, नहीं। रिकल केस के बाद एक वातावरण बना, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स संगठन सक्रिय हुए और पाकिस्तान में माइनेस्ट्रीज, जो हिन्दू वहां रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ हिन्दू प्रेशान है, वहां पांसी भी प्रेशान हैं। मंत्री जी, वहां ईसाई भी प्रेशान हैं। ... (ल्यवधान) जितने भी पाकिस्तान में माइनेस्ट्रीज हैं, वे सब प्रेशान हैं। ... (ल्यवधान) शतपात महाराज जी आप सही कठ रहे हैं, मैंने तो पहले ही बोता है कि वहां किंशन भी प्रेशान हैं। ... (ल्यवधान) जोशी जी, मुस्लिम कम प्रेशान हैं। ... (ल्यवधान) यादव साहब, आप तो राजस्थान के प्रभारी हो, आप एक बार जोधपुर जाकर तो देखो कि उनकी हालत वया है? ज्योति जी, शायद आप तो जोधपुर गये होंगे। ... (ल्यवधान) नहीं, नहीं, बाकी तोग इतने प्रेशान नहीं हैं, ये वाकई मैं बहुत प्रेशान हैं और इनकी प्रेशानी हमें मानवीय आधार पर ढल करनी चाहिए। मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि इसकी पॉवर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वयों नहीं दे सकते? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लोग कठते हैं कि नो, नो, नो वी कैन नॉट डेलिवर इट, वयों आई? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले नागरिकता देते थे, जो एमएवाए ने रूल्स और ऐज्युकेशन बनाये हैं, ये उसी के तहत तो देंगे। एमएवाए रूल बनाता है तो बन्दूक का लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है, वह बन्दूक लेकर किसी को मार भी सकता है, फिर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर आप रिटार्ड करते हो। नागरिकता देने की पॉवर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं दे सकते, नागरिकता देने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पॉवर वयों नहीं दे सकते? मेरा यह कठना है। आप कठ रहे हैं कि हमने वर्ष 2004 में दिया, वर्ष 2007 में दिया, अब नहीं देंगे, इसका आपने कोई आशासन नहीं दिया।

आपने फीस बढ़ायी। आपने फीस किसके लिए बढ़ायी? ये पाकिस्तान से भागे हुए तोग हैं। ये जबरदस्ती यहां आ गये या कोई आतंकवारी है, कोई अनेस्ट फैला रहे हैं।

या कोई अव्यवरथा फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है...(व्यवधान) वे बढ़ी हुई फीस नहीं दे सकते हैं। ये अधिकतर वीकर सैक्षण ऑफ टी सोसायटी के लोग हैं। अब जो वहां पाकिस्तान में रह गये हैं, ये वह लोग हैं। आपने बहुत फीस बढ़ा दी है। यह सुझाव, सलाह आपको किसने दी? आप कम से कम फीस तो वापस ले लो, जो पुणी फीस है, उसमें बात कर लो। आज अगर एक फैमिली में पांच लोग हैं, तो उनको तारख, सवा तारख रूपये फीस देनी पड़ती है, उनके पास फीस नहीं है। मैं उनसे मिला था कि आपको इस फीस में वया प्रैवल्य है, तो उन्होंने कहा कि छम तो वैसे ही बेधर है, हमारे पास कोई घर नहीं है। छम अगर नागरिकता भी लेने जायें तो डेढ़ तारख रूपये कठां से लायेंगे तो छम फार्म भी नहीं भर सकते। मंत्री जी, आप थोड़ा मानवीय आधार पर योतिहारे। मंत्री जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं एक बार आपसे मिला हूं, आपमें मानवीय आधार पर योतिहार सोच है तो फिर आप इस मामले में वयों नहीं सोच रहे हो? आपको किसी ने ऐसा कह दिया है कि ऐसा मत सोचो तो आप ज्यादा उन पर डिपेंड मत रहो, आप अपने विवेक के आधार पर निर्णय करो। अभी इन्होंने वया किया, जब यह बिन्दु छमने यहां उठाया, इसके बाद इस्लामाबाद में एक एवशन हुआ। वया हुआ, भारतीय दूतावास, यह तो आपका ही है, विशेष मंत्रालय के लोग यहां बैठे होंगे...(व्यवधान) यह सरकार का है, मेरा तो है ही, सबका है। मैंने जलती मान ली है, इनको नागरिकता दिला दो तो आप जो कहेंगे, वह छम मानेंगे। ...(व्यवधान) यहां इजराज सिंह जी भी बैठे हैं, आप जो कहेंगे, छम उसे मानेंगे। मैं कह रहा हूं कि इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास वीजा नहीं दे रहा है। अब जो लोग आ रहे हैं, उन्हें वीजा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बहुत जटिलताएं पैदा कर दी हैं। डिवाइडेट फैमिली में अगर कोई मेंबर मर जाता है तो भी उन्हें वीजा नहीं देते हैं। कुछ डिवाइडेट फैमिली हो गई, कोई यहां रह गया, कोई पाकिस्तान चला गया। अब कोई कहता है कि मेरे फादर की मृत्यु हो गयी, अपना वह जो भारतीय दूतावास का आदमी है, वह यह कहता है कि किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर लाओ कि आपके फादर की डेथ हो गयी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आप वया आदेश जारी करते हैं? वह आदमी कठां से लाएगा? गजटेड ऑफिसर से वेरिफाई कराने के लिए, आप इस तरह की जटिलताएं पैदा मत करिए। जब छम ने यह विषय उठाया तो आपने एक और जटिलता पैदा कर दी। लोग जोधपुर में ही परेशान नहीं हैं बल्कि ऐलनाबाद और इंदौर में भी लोग परेशान हैं। आपने गुजरात में ताँग टर्म वीजा की बात कही, उनके रोजगार की बात कही। अभी-अभी जोधपुर में एक केस आया, बट्री जी यहां बैठे हैं वे जानते हैं। सनलाइट हॉस्पिटल में सिंध से रटडी किए हुए कुछ डॉक्टर्स काम करते थे उनको निकात दिया गया। उनको बोला गया कि आप लोग तो पाकिस्तानी हैं। वे आप के पास भी आए होंगे। ये हमारे सब साथी हमारे समर्थन के लिए बैठे हैं। ये हमारे अगेनरेट में नहीं हैं। हमारे साथी हमारे समर्थन में वोट करेंगे। ...(व्यवधान) अभी मंत्री जी ने जो एंड के के एक विषय में कठा कि वहां के उस समय के मुख्यमंत्री जी ने कठा था कि आप जम्मू-कश्मीर में रहिए। छम आपको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। जो जम्मू-कश्मीर से पंजाब आ गए, वे इस देश का प्रधान मंत्री बन सकते हैं। मंत्री जी जो जम्मू-कश्मीर में रह गए उनकी वया गतली हैं। आप उनको दो एकड़ लैंड दे रहे हैं। 65 साल में उनकी फैमिली बड़ी हो गई तो वे दो एकड़ लैंड में वया करेंगे? आपकी क्रेडिट गारंटी रकीम के तहत उनको लोग भी नहीं मिलता है, वे नागरिक नहीं हैं। आप कौन सी रकीम के तहत उनको लोग दे रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। वे नागरिक नहीं हैं। हमारा यह कठना है कि उनकी कोई गतती नहीं थी। उस समय के मुख्य मंत्री ने कठा कि आप लोग यहां रहिए, छम आप को सारी सुविधाएं देंगे। वे बेतारे वहां रह गए। लाल सिंह चौधरी जी यहां नहीं हैं वे कठते हैं कि वे एमपी के चुनाव में वोट दे सकता है, लेकिन वे एमएलए के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। वे चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, वोट डाल नहीं सकते हैं, ऐसी काहे कि नागरिकता है? अगर धारा 370 आड़े आती है तो इसमें भी संशोधन करना चाहिए। हां(व्यवधान) सतपाल महाराज जी कह रहे हैं कि वे निकाय के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। हमारे सभी साथी सदन में मेरे साथ हैं। सभापति महोदया, आप भी मेरे साथ हैं, मंत्री जी भी साथ हैं तो यह संक्षेप वयों नहीं पास हो रहा है? मेरा यह यक्षा प्रश्न आप के माध्यम से है।

सभापति महोदया: वया आप यह प्रिदृश्य कर रहे हैं?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मंत्री जी कुछ आश्वासन देंगे, तभी प्रिदृश्य करूँगा।

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Meghwali, all these points that you have raised right now, you had, in fact, raised them on the day when you had moved the Resolution also. I have covered almost all the points in my reply.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: You have covered them but you have not given any assurance to me.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: What assurance can I give you?

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I want refugee status for them. Would you give them refugee status?

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: At the moment, we cannot consider that issue at all.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: What is your action plan regarding citizenship?

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: There is absolutely no problem about citizenship. I have made it absolutely clear.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Can you give this power to the District Magistrate of the concerned District?

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: As of now, there is absolutely no problem regarding citizenship at all for the people who have come from Pakistan.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: You have to give some assurance to me. सतपाल महाराज जी कह रहे हैं कि मैं मंत्री होता तो यह दे देता है।(व्यवधान)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: If you have got any specific problem, you can let me know. I will look into that. I will correct it.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: It is not a specific problem but it is a general problem. My point is that you are not giving refugee status to the Pakistani minority which is coming here.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: We cannot give refugee status.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: You are not providing citizenship. You are providing the citizenship but the process is very complicated.

MADAM CHAIRMAN : You only request him to withdraw.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Meghwali, with all humility at my command, I would request you to withdraw the Resolution.

MADAM CHAIRMAN: Are you withdrawing the Resolution?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मंत्री जी आप कुछ तो आव्यासन दीजिए तो मैं यह विद्वान् कर तूँगा। हॉ(व्यवधान)

सभापति महोदया : धन्यवाच।

â€“(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं इसे विद्वान् कर सकता हूँ लेकिन मेरी आत्मा यह एलाउ नहीं कर रही है इसलिए मैं अपनी आत्मा के अनुसार सदन में आचरण करूँगा। हॉ(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"Taking into account the problems being faced by the persons migrated from Pakistan to India and settled in various parts of the country, this House urges upon the Government to take immediate steps to grant them citizenship and formulate a time bound action plan to extend them facilities as are available to other citizens of the country."

The motion was negatived.
